NYCS

युवा सहकार

www.nycsindia.com

अक्टूबर 2024, नई दिल्ली

रोजगार का नया केंद्र

सहकारिता

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives, Always!

LIFIC

LINAC-NCDC FISHERIES BUSINESS INCUBATION CENTER (LIFIC)

For Cooperatives as Fisheries Bussiness

Set up by NCDC at LINAC
under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
Department of Fisheries,
Ministry of Fisheries, AH & D, Govt of India

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
National Cooperative Development Corporation
Ministry of Cooperation, Govt of India

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-04, अक्टूबर-2024

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं पारस ऑफसेट प्रा. लि. कुंडली, हरियाणा द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

सहकारिता बढ़ाएगी रोजगार 04

कभी बिकने की थी नौबत, अब बनाया मुनाफे का रिकॉर्ड 05

06 रोजगार का नया केंद्र सहकारिता

14 खुद को बदलें सहकारी समितियां : मुर्मू

सहकारिता में युवाओं की ज्यादा भागादारी से भारत... 16

छोटे लोगों का बड़ा बैंक 18

युवाओं को सहकारिता से जोड़ने में जुटा कृभको 20

कौशल से सशक्त युवा ही बनाएंगे विकसित भारत 22

पुणे में अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू 24

पर्यटन कौशल से लैस होंगे 20 हजार युवा 25

क्रेडिट सोसायटियों से मिलेगा दोगुना लोन 27

गांवों में होमस्टे से खुले रोजगार के अवसर 28

सहकारिता बढ़ाएगी रोजगार

सहकारिता क्षेत्र ने रोजगार और स्वरोजगार को लेकर नई आशाएं जगाई हैं। सहकारिता क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की पूरी क्षमता है। सरकार का भी जोर सहकारिता के माध्यम से समृद्धि बढ़ाने पर है। सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र का विस्तार होने के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं।

भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में रोजगार के नए-नए अवसर पैदा करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। इसे लेकर समय-समय पर हंगामा होता है। सच्चाई यह भी है कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती और निजी क्षेत्र घरेलू या वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती आते ही छंटनियों का दौर शुरू कर देता है जिससे समस्या और बढ़ जाती है। ऊपर से टेक्नोलॉजी ने भी नई नौकरियों के लिए चुनौती पैदा की है। स्वरोजगार को लेकर भी अभी भारतीय युवाओं की मानसिकता उस तरह की नहीं बन पाई है, जैसी जरूरत है। खासकर, मध्यवर्गीय युवा पढ़-लिख कर स्वरोजगार की बजाय नौकरी करना ज्यादा पसंद करता है। हालांकि, इस मानसिकता में बदलाव हो रहा है लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। जो युवा स्वरोजगार करना भी चाहते हैं उन्हें पूंजी की समस्या से लेकर मार्केटिंग तक तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे कई बार वह भी इसे छोड़कर नौकरी करना ज्यादा आसान समझते हैं।

ऐसे में सहकारिता क्षेत्र ने रोजगार और स्वरोजगार को लेकर नई आशाएं जगाई हैं। सहकारिता क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की पूरी क्षमता है। सरकार का भी जोर सहकारिता के माध्यम से समृद्धि बढ़ाने पर है। सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र का विस्तार होने के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। इनमें जन औषधि केंद्र से लेकर पेट्रोल व गैस पंप, रसोई गैस एजेंसी और कॉमन सर्विस सेंटर जैसे क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, डेयरी एवं फिशरीज और सहकारिता में सहकार को बढ़ावा देने के सरकार के कदमों से रोजगार की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि, इन प्रयासों के नतीजे आने में अभी समय लगेगा। लेकिन यह भी तथ्य है कि अगर सहकारी क्षेत्र में इन प्रयासों को पूरी गंभीरता से अमल में लाया गया तो यह ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को रोकने में भी मददगार साबित होगा।

डेयरी क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में जहां नई डेयरी सोसायटियों का गठन कर उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प सरकार ने व्यक्त किया है, वहीं मत्स्य क्षेत्र में इसका विस्तार किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन में कोऑपरेटिव सेक्टर की भागीदारी 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रत्येक गांव तक डेयरी सहकारी सोसायटी के गठन पर जोर दिया गया है। इसके लिए श्वेत क्रांति 2.0 लांच की गई है। सहकारिता में सहकार की भावना के तहत कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत बनाने की पहल की गई है। इसके तहत सभी सहकारी संस्थाओं का खाता कोऑपरेटिव बैंकों में खोलने का निर्देश दिया गया है। गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लागू करने के बाद अब इसे पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया है।

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ मिलकर कौशल विकास के कई कार्यक्रम चला रही है। इसका फायदा निश्चित तौर पर युवाओं को मिल रहा है। एनवाईसीएस का ध्येय युवा विकास से राष्ट्र का विकास करना है। युवाओं का कौशल विकास करने से न केवल उनके जीवन में समृद्धि आएगी, बल्कि वे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भी भागीदार बन सकेंगे। ■

प्रकाश चंद्र साहू

अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

मालामाल हुई नैफेड

कभी बिकने की थी नौबत, अब बनाया मुनाफे का रिकॉर्ड

युवा सहकार टीम

बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। खेती और उससे जुड़े उत्पादों की मार्केटिंग करने वाला नैफेड यानी भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ के बिकने की नौबत आ गई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे बेचने के निर्णय पर मुहर भी लगा दी थी। और अब स्थिति इसके एकदम उलट है। नैफेड का पूरी तरह कायापलट हो चुका है और सहकारी क्षेत्र में यह एक नजीर बन गया है। अपने कुप्रबंधन की वजह से नैफेड के घाटे का दौर 2005 से 2016 तक दस वर्ष से अधिक समय तक चला। इस सहकारी संस्था के दिन बहुरने की शुरूआत वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित नई सरकार बनने के बाद हुई। सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने का फैसला लिया। प्रबंधन की खामियों को दूर कर सख्ती बरती गई और इसे पटरी पर लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। नतीजतन नैफेड ने वित्त वर्ष 2023-24 में 492.38 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। नैफेड के अब तक के इतिहास में यह सबसे ज्यादा मुनाफा है। इस दौरान टर्न ओवर 26,520 करोड़ रुपये रहा। साथ ही 15 प्रतिशत लाभांश देने की घोषणा नैफेड की ओर से की गई है।

नैफेड के चेयरमैन जेठाभाई अहीर ने नैफेड की 67वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए सहकारिता के विकास में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में पहला सहकारिता मंत्रालय बनने के

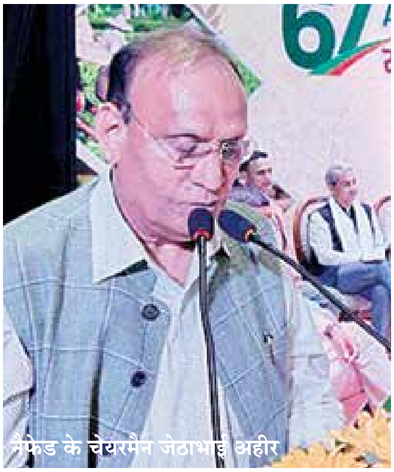

नैफेड के चेयरमैन जेठाभाई अहीर

बाद सहकारिता के क्षेत्र में निरंतर तरक्की हो रही है। पहले सहकारिता मंत्री के रूप में श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में बेहद कम समय में सहकारिता ने विश्वस्तरीय उपलब्धि हासिल की है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित कर रही हैं। मत्स्य, डेयरी, पशुपालन, भंडारण वितरण आदि कार्यों में भी सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ी है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने ई-समृद्धि पोर्टल से अधिक से अधिक किसानों के जुड़ने की अपील की। इसी उद्देश्य से वार्षिक आम सभा में पंजीकरण काउंटर भी लगाया गया।

नैफेड की उपलब्धि को देखते हुए श्री जेठाभाई अहीर ने फेडरेशन के सदस्यों में 15 प्रतिशत लाभांश वितरित करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से किसान कल्याण योजनाओं को बिना किसी बाधा के लागू किया जा रहा है।

नैफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक रितेश चौहान ने कृषि क्षेत्र में किए गए नवाचारों के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि नैफेड ई-समृद्धि पोर्टल के माध्यम से किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है जिसका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 4 जनवरी, 2024 को किया गया था। पोर्टल पर अब तक 17.5 लाख किसान पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण कराने वाले किसानों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नैफेड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों का जीवन बेहतर बनाया जा रहा है। ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत भारत ब्रांड के उत्पादों की लॉन्चिंग भी इसी योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर किसानों की उपज के लिए एक विश्वसनीय बाजार बनाना है। चौहान ने फेडरेशन के पदाधिकारियों से कहा कि सदस्यों के निरंतर सहयोग से नैफेड को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है।

वार्षिक आम सभा की बैठक में 600 से अधिक पदाधिकारयों व विभिन्न सहकारी समितियों के सदस्यों व बोर्ड निदेशकों ने भाग लिया। एजीएम में विभिन्न सहकारी समितियों को वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नैफेड की पहलों को अगले चरण तक ले जाने के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में देशभर के किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि, पैक्स प्रतिनिधि व किसान कल्याण समितियों के सदस्य भी उपस्थित थे। ■

रोजगार का नया केंद्र सहकारिता

सहकारिता से बदल रही तस्वीर, युवाओं के रोजगार का बड़ा माध्यम बना

पैक्स के ऑनलाइन होने से युवाओं के लिए खुलेंगे नए द्वार

सरकार के सौ दिन में सहकारिता क्षेत्र को मिली कई सौगातें

श्वेत क्रांति 2.0 की शुरूआत, नंबर वन दुग्ध उत्पादक बनने के बाद निर्यात बढ़ाने की तैयारी

अभिषेक राजा

बीते कुछ वर्षों से देश में रोजगार को लेकर चर्चा बेहद गर्म है। कुछ कुछ अंतराल के बाद देश में हो रहे चुनावों ने बेरोजगारी या नौकरियों की कमी को सियासी जामा पहना दिया है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग और काम धंधे वाले क्षेत्रों में सरकारों की हिस्सेदारी कम होने से नई नौकरियों की संख्या भी घटी है। उस पर निजी क्षेत्र में हो रही छंटनी ने देश में बेरोजगारी की समस्या को और चिंताजनक बना दिया है। बीते दिनों तेजी से उभर रहे मोबाइल हैंडसेट निर्माण क्षेत्र से लेकर बैंकिंग और आईटी सेक्टर में कई कंपनियों ने नौकरियों में कमी करने का ऐलान कर स्थिति को और गंभीर बना दिया है। देश में मैन्यूफैक्चरिंग की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। इन विकट परिस्थितियों में एक सेक्टर ने इधर युवाओं के लिए नए रोजगार के सृजन की आशा जगाई है। यह सेक्टर है कोऑपरेटिव यानी सहकारिता। वर्ष 2019 में

देश में रोजगार का हाल

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो देश में रोजगार के मामलों पर नजर रखती है। सीएमआई की एक रिपोर्ट कहती है कि जून 2024 में भारत में बेरोजगारी दर मई 2024 की 7 फीसदी के मुकाबले बढ़कर 9.2 फीसदी हो गई। जून 2024 में महिलाओं की बेरोजगारी दर 18.5 फीसदी पर पहुंच गई, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जून 2023 में महिला बेरोजगारी दर 15.1 फीसदी थी। पुरुष बेरोजगारी दर की बात करें, तो यह जून 2023 के 7.7 फीसदी के मुकाबले बढ़कर 7.8 फीसदी हो गई। इसी तरह, शहरी बेरोजगारी की दर जून में 9.3 फीसदी हो गई जो मई में 6.3 फीसदी थी। सीएमआईई के 2008 से 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में देश में सबसे कम 5.27 फीसदी लोग बेरोजगार थे। 2021 से बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2008 से 2020 के दौरान बेरोजगारी दर 5.6 फीसदी के आसपास रही।

सीएमआईई के श्रम भागीदारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2023 में जहां देश के 39.9 फीसदी लोग रोजगार लायक थे, वहीं जून 2024 में उनकी संख्या बढ़कर 41.4 फीसदी पर पहुंच गई। इस आंकड़े से पता चलता है कि अब लोग पहले से ज्यादा काम की तलाश में हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में रोजगार के मुकाबले पढ़े-लिखे युवाओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। पढ़े-लिखे युवा कम वेतन वाली नौकरी करना नहीं चाहते और खाली बैठना बेहतर समझते हैं, इसलिए उनमें बेरोजगारी ज्यादा है। ऐसे युवा खुद का काम-धंधा शुरू करने का प्रयास करते हैं जिसमें समय लगता है। तब तक उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है। आईएलओ के आंकड़ों के अनुसार, भारत की 83 फीसदी युवा आबादी इसीलिए बेरोजगार है।

आईएलओ और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की संयुक्त रिपोर्ट इंडिया एम्पलॉयमेंट रिपोर्ट-2024 के मुताबिक, वर्ष 2000 से 2022 के बीच भारत में पढ़े-लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या दोगुनी हो गई। 2000 में जहां केवल 35.2 फीसदी पढ़े-लिखे युवा ही बेरोजगार थे, वहीं 2022 में उनकी संख्या 65.7 फीसदी पर पहुंच गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 से 2018 के बीच देश में रोजगार की स्थिति ज्यादातर खराब ही रही। 2019 में स्थिति में सुधार देखने को मिला, लेकिन 2020 में हालात फिर से बिगड़ गए। रोजगार की स्थिति में सुधार न होने का मुख्य कारण गैर कृषि क्षेत्र जैसे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र आदि में विकास की धीमी रफ्तार रहना बताया गया है।

भारत में औसतन 90 फीसदी रोजगार असंगठित क्षेत्र मे हैं। असंगठित क्षेत्र अनपढ़, कम पढ़े-लिखे, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित, कुशल और अकुशल सभी तरह के लोगों को काम देने में सक्षम है। लिहाजा रोजगार का दारोमदार असंगठित क्षेत्र पर ज्यादा है।

सरकार की तरफ से सहकारिता के लिए एक नया और अलग मंत्रालय गठित होने के बाद इस क्षेत्र ने युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार भी खोले हैं।

सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र का विस्तार होने के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। इनमें जन औषधि केंद्र से लेकर पेट्रोल व गैस पंप, रसोई गैस एजेंसी और कॉमन सर्विस सेंटर जैसे क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। बड़ी सहकारी समितियों के अतिरिक्त देश के कोने-कोने में व्याप्त सहकारी समितियों और पैक्स ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू भी किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन प्रयासों के नतीजे आने में अभी समय लगेगा। लेकिन यह भी तथ्य है कि अगर सहकारी क्षेत्र में इन प्रयासों को पूरी गंभीरता से अमल में लाया गया तो यह ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को रोकने में भी मददगार साबित होगा। कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़ने की धीमी रफ्तार वर्तमान में गांवों से युवाओं के शहरों की तरफ पलायन को निरंतर प्रेरित करती रही है।

सरकार का लक्ष्य है कि सहकारिता देश में रोजगार देने वाला प्रमुख क्षेत्र बने। देश की शीर्ष सहकारी संस्था भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी ने युवा सहकार से बातचीत कहा, 'सहकारिता क्षेत्र रोजगार बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम है। सहकारिता क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने और दुनिया को नई दिशा दिखाने की क्षमता है। आज

सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र का विस्तार होने के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। इनमें जन औषधि केंद्र से लेकर पेट्रोल व गैस पंप, रसोई गैस एजेंसी और कॉमन सर्विस सेंटर जैसे क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं।

> **युवा विकास से राष्ट्र विकास के सूत्र को अपना ध्येय मानते हुए एनवाईसीएस देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने और ऐसे सभी मौकों से अवगत कराने का प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल उनके जीवन में सुधार होगा बल्कि वे राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भागीदारी कर सकेंगे।**

दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसमें बिना खून बहाए सहकारिता आंदोलन से ही पूरे विश्व में समृद्धि का द्वार खोला जा सकता है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।' जानकारों का मानना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बहुत जरूरी है। सहकारिता क्षेत्र की एपेक्स बॉडी होने के नाते एनसीयूआई ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। इसके लिए एनसीयूआई ने युवा कमेटी बनाई है ताकि सहकारिता से जुड़े हर मोर्चे पर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जा सके। साथ ही राज्यों में युवाओं को सहकारिता से जोड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है।

सरकार का भी जोर युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और इसके माध्यम से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर है। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र साहू कहते हैं, 'युवा विकास से राष्ट्र विकास के सूत्र को अपना ध्येय मानते हुए एनवाईसीएस देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने और ऐसे सभी मौकों से अवगत कराने का प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल उनके जीवन में सुधार होगा बल्कि वे राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भागीदारी कर सकेंगे।' अन्य सहकारी समितियों की भांति इफको भी कौशल विकास और टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ाकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि का जिक्र करते हुए कहा, 'इफको देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और किसानों व सहकारिता के लिए कार्य करती रहेगी। हम सहकार से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए भारत को शीर्ष पर स्थापित करेंगे।'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने उल्लेखनीय पहल की है, जिसके नतीजे दूरगामी साबित होंगे। 'सहकारिता में सहकार' अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करना है। सहकारिता क्षेत्र में सरकार ने तीन नई समितियों राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का गठन किया है। ये समितियां रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

श्वेत क्रांति 2.0 और प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पैक्स की पहुंच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन तीन प्रमुख अभियानों की शुरुआत से सहकारी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जिसका फायदा निश्चित तौर पर युवाओं को मिलेगी। नाबार्ड से पैक्स, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) से डेयरी और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड (एनएफडीबी) से मत्स्य क्षेत्र को वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराई जा रही है। डेयरी क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में जहां नई डेयरी

रोजगारपरक 19 सरकारी योजनाएं

भारत सरकार ने रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए कर्ज देने वाली 19 योजनाएं चला रखी हैं। इन योजनाओं में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट, नेशनल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शामिल हैं। इनके अलावा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पीएम स्वनिधि स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएं भी हैं जो इनमें मददगार हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई), पीएम गतिशक्ति, इंडियन फुटवियर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स तथा फ्यूचर स्किल्स प्राइम नाम की योजनाएं भी रोजगार के मौके और संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

सोसायटियों का गठन कर उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने को संकल्प सरकार ने व्यक्त किया है, वहीं मत्स्य क्षेत्र में इसका विस्तार किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन में कोऑपरेटिव सेक्टर की भागीदारी 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रत्येक गांव तक डेयरी सहकारी सोसायटी के गठन पर जोर दिया गया है। इसके लिए श्वेत क्रांति 2.0 लांच कर दी गई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह ने डेयरी क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पर जोर दिया है। इसमें घरेलू स्तर पर निर्मित होने वाली मशीनों का उपयोग किया जाएगा। इससे इन मशीनों के निर्माण क्षेत्र में भी युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पैक्स के कंप्यूटरीकरण से युवा हो रहे लाभान्वित

देश के सुदूर क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पैक्स) पहुंचाने का अभियान शुरू हो चुका है, जिसे इन सौ दिनों में और रफ्तार दी गई है। इससे अब कोई गांव अछूता नहीं रह जाएगा। सहकारिता में शुरू की गई कारोबारी गतिविधियों को विस्तार दिया जा रहा है। इस संबंध में श्री शाह ने कहा कि पैक्स को 25 अलग-अलग कामों से जोड़कर उन्हें व्यवहार्य बना दिया है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में ही 22,000 से अधिक पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। सरकार ने 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 67,930 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य रखा है। 30 अगस्त, 2024 तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 31,301 पैक्स ईआरपी सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। इसका सीधा फायदा युवाओं को रोजगार के रूप में मिल रहा है क्योंकि इन पैक्सों में कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले ज्यादातर युवा ही हैं। वित्त वर्ष

दुग्ध उत्पादन में कोऑपरेटिव सेक्टर की भागीदारी 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रत्येक गांव तक डेयरी सहकारी सोसायटी के गठन पर जोर दिया गया है। इसके लिए श्वेत क्रांति 2.0 लांच कर दी गई है।

सहकारिता मंत्रालय की सौ दिनों की कार्य योजना

- श्वेत क्रांति 2.0 की लांचिंग
- सहकारिता में सहकार अभियान को देशव्यापी बनाया गया
- पैक्स कंप्यूटरीकरण को मिली रफ्तार, 22 हजार से अधिक पैक्स हुए कंप्यूटरीकृत
- डेयरी व मत्स्य क्षेत्र की पैक्स को हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय
- राष्ट्रीय सहकारी जैविक सोसायटी का जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड से समझौता
- असम और नगालैंड के एफपीओ से राजमा, ब्लैक और रेड राइस खरीदने का समझौता
- भारतीय बीज सहकारी सोसायटी का आइसीएआर से मक्का के ब्रीडर बीज के लिए समझौता
- सहकारी चीनी मिलों को मक्का समेत अन्य वस्तुओं से एथनॉल उत्पादन के लिए वित्तीय मदद का फैसला
- राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2024 तैयार

सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के माध्यम से देश के कुल दूध उत्पादन में डेयरी कोऑपरेटिव की हिस्सेदारी में अगले पांच वर्षों में 50% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। अभी यह हिस्सेदारी 14% है जिसे बढ़ाकर 22% किया जाना है।

2024-25 के आम बजट में सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे राज्यों को पैक्स के कंप्यूटरीकरण में आर्थिक बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहकारिता क्षेत्र में किए गए कानूनी सुधार के तहत प्रत्येक राज्य ने केंद्र सरकार के बनाए गए पैक्स में मॉडल बायलॉज को लागू कर दिया है।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में केंद्रीय सरकारिता मंत्रालय की 10 पहलों को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने दो लाख नए पैक्स, 'प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण पर मार्गदर्शिका' लांच कर श्वेत क्रांति 2.0' और 'सहकारिता में सहकार' पर मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। श्वेत क्रांति 2.0 को लांच करते हुए उन्होंने कहा कि इससे महिला स्वावलंबन और उसके सशक्तीकरण के साथ-साथ कुपोषण के खिलाफ जंग को भी ताकत मिलेगी और रोजगार की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

डेयरी में युवाओं के लिए बढ़ीं संभावनाएं

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले सहकारी डेयरी क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। सहकारिता मंत्रालय की पहल से पशुपालकों का जीवन स्तर सुधर रहा है। सरकार का लक्ष्य श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से अब इसे और आगे ले जाने का है। सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के माध्यम से देश के कुल दूध उत्पादन में डेयरी कोऑपरेटिव की हिस्सेदारी में अगले पांच वर्षों में 50% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। अभी यह हिस्सेदारी 14% है जिसे बढ़ाकर 22% किया जाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने के पहले 100 दिन में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री शाह ने इस लक्ष्य को पूरा करने वाले

अभियान की शुरुआत की। सरकार का दावा है कि इस क्रांति के माध्यम से युवाओं के लिए डेयरी क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। सहकारी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि निजी डेयरी क्षेत्र को भी इसका फायदा मिलेगा। सरकार का जोर अब दुग्ध और इसके उत्पादों का निर्यात बढ़ाने पर है। श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा जिसमें निजी क्षेत्रों की भी अहम हिस्सेदारी होगी।

दुग्ध क्षेत्र में आत्मनिर्भर

दुग्ध क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। भारत का वार्षिक दुग्ध उत्पादन 23 करोड़ टन से अधिक हो गया है जिसकी बदौलत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 24.64 प्रतिशत हो गई है। इसके बावजूद देश के कुल दुग्ध उत्पादन में सहकारिता क्षेत्र की हिस्सेदारी 14-15 प्रतिशत ही है। इसे बढ़ाकर अगले पांच वर्ष में 22-23 प्रतिशत करने की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) इस योजना की नोडल एजेंसी होगी। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों को डेयरी सहकारिता से जोड़ा जा सकेगा। वर्तमान में देश के आठ करोड़ से अधिक किसानों की रोजी रोटी डेयरी सहकारिता से जुड़ी है। सहकारिता मंत्रालय की पहल से ग्रामीण पशुपालकों और भूमिहीन किसानों को सहकारी क्षेत्र की डेयरी से उनकी आमदनी को बढ़ाने में मदद मिली है। पांच प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहे डेयरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। गरीब ग्रामीणों, भूमिहीन व छोटे किसानों की आमदनी का प्रमुख साधन बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने डेयरी क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी समितियों के गठन का अभियान भी शुरू किया है। यह क्षेत्र जहां आठ करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है वहीं अप्रत्यक्ष रूप से इससे कहीं अधिक रोजगार सृजित होता है।

श्वेत क्रांति 2.0 का फायदा सिर्फ सहकारिता क्षेत्र को ही नहीं मिलेगा, बल्कि निजी क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होगा। देश में डेयरी की 75 हजार से अधिक सहकारी समितियां ठप पड़ी हैं। उन्हें भी सक्रिय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले कई सालों में जब से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला है, डेयरी क्षेत्र में भी कई स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। ये स्टार्टअप्स डेयरी फार्म के संचालन से लेकर उपभोक्ताओं को सीधे दूध की सप्लाई कर रहे हैं। इनमें कंट्री डिलाईट, मिल्क मंत्रा, फार्मरी, बरोसी, हैप्पी मिल्क, डूजी हैप्पी नेचर, द मिल्क इंडिया और द गुड काउ कंपनी शामिल हैं जो न सिर्फ डेयरी फार्म से सीधे उपभोक्ताओं को दूध की सप्लाई करती हैं, बल्कि गुणवत्ता वाले दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इन्होंने खुद का डेयरी फार्म स्थापित किया है। इन्होंने डेयरी-टू-कंज्यूमर का मॉडल अपनाया है। इसी तरह, मिल्क बास्केट, डेली निंजा और इन्सेनली गुड (पहले सुपर डेली) जैसे नए जमाने के हाइपरलोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैं जो दूध की डिलीवरी करते हैं। इन स्टार्टअप्स को शुरू करने वाले ज्यादातर टेक्नोक्रेट्स युवा हैं। इनमें लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है।

कोऑपरेटिव बैंकों में बढ़ेंगी नौकरियां

सहकारी बैंकिंग को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने सभी तरह की सहकारी समितियों का बैंक खाता कोऑपरेटिव बैंकों में खोलने का निर्देश दिया है। इस देशव्यापी कदम से

श्वेत क्रांति 2.0 का फायदा सिर्फ सहकारिता क्षेत्र को ही नहीं मिलेगा, बल्कि निजी क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होगा। देश में डेयरी की 75 हजार से अधिक सहकारी समितियां ठप पड़ी हैं। उन्हें भी सक्रिय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्वेत क्रांति 2.0 के लाभ

- छोटे और युवा डेयरी किसानों को बाजार की पहुंच प्राप्त होने के साथ उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा
- प्राथमिक डेयरी सहकारिताओं के नेटवर्क को आगे बढ़ाने तथा दूध संकलन, परीक्षण, चिलिंग, लॉजिस्टिक और प्रसंस्करण अवसंरचना सहित संपूर्ण डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी
- दूध संकलन में वृद्धि होने से डेयरी उद्योग में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी
- खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने और ताजा तथा स्वच्छ दूध एवं दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी
- डेयरी क्षेत्र के विकास और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ निर्यात करने की क्षमता भी बढ़ेगी
- महिलाओं की सदस्यता को अधिक बल मिलेगा जो डेयरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण हितधारक हैं

न सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी, बल्कि उनका कारोबार भी कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन बैंकों का कारोबार बढ़ेगा तो नौकरियों के नए अवसर भी बढ़ेंगे। देश के करीब 30 करोड़ लोग सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं। ऐसे में यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर इन सभी लोगों का खाता या इनमें से आधे लोगों का खाता भी कोऑपरेटिव बैंक में खुलेगा तो इन बैंकों का कारोबार कितना बढ़ जाएगा। इसके अलावा, सभी तरह के पैक्स और अन्य सहकारी समितियों के भी खाते कोऑपरेटिव बैंक में खुलने से गांवों और दूरदराज के इलाके में स्थित इन बैंकों के कारोबार में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है।

किसानों और डेयरी क्षेत्र में लगे पशुपालकों को आर्थिक रूप से सबल बनाने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट को पहले गुजरात के दो जिलों और फिर पूरे गुजरात में चलाया गया था जिसे जबर्दस्त सफलता मिली है। इसकी सफलता को देखते हुए अब इसे देशव्यापी बना दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को वित्तीय लेन-देन के लिए सदस्यों को माइक्रो एटीएम कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। सरकारिता से जुड़े सभी लोगों के बैंक खाते सहकारी बैंकों में ही खोले गए। इसके तहत सीमित अवधि में ही दोनों जिलों में चार लाख से अधिक बैंक खाते सहकारी बैंकों में खोले गए और 750 करोड़ रुपये की धनराशि जमा की गई। जबकि पूरे गुजरात में 9.40 लाख खाते खोले गए और 3,853 करोड़ रुपये की धनराशि जमा हुई। इससे सहकारी बैंकों के साथ उनसे जुड़े लोगों को काफी लाभ हुआ है। इसे गुजरात के दो प्रमुख जिले बनासकांठा और पंचमहल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था। एक साल के भीतर ही इसे पूरे राज्य में शुरू कर दिया गया और अब सरकार ने इस महत्वकांक्षी योजना को पूरे देश में लागू कर दिया है। इस परियोजना के शुरू होने से सहकारी समितियों का वित्तीय लेन-देन आसान होगा। इस अभियान का उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को केंद्रीय जिला सहकारी बैंक और राज्य स्तरीय सहकारी बैंक के माध्यम से विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना है, जिससे सदस्यों को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हो सकें। इस परियोजना में सभी सहकारी समितियां शामिल होंगी। परियोजना के शुरू होने के दो महीने के भीतर बैंक मित्रों की नियुक्ति और रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने आदि का काम पूरा कर लिया जाना तय किया गया है। देशभर में बैंक मित्रों की नियुक्ति से लाखों युवा लाभान्वित होंगे।

फिशरीज में भी मिलेंगे नए मौके

भारत का करीब 7,500 किलोमीटर इलाका समुद्र तटीय है। इस इलाके में रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका का मुख्य साधन समुद्र से मछली पकड़ना है। इसके अलावा, देश के भीतर लाखों हेक्टेयर जमीन जलीय है जिनमें मछली पालन होता है। यह क्षेत्र 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान कर रहा है। इनमें वंचित तबके के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिशरीज से जुड़े इन लोगों को अब तक सरकार की ओर

से किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही थी, लेकिन सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सरकार ने फिशरीज पैक्स बनाने का भी निर्णय लिया। मत्स्य पालन सहकारी समितियों सहित दो लाख नई प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना की यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ एवं राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

सहकारी क्षेत्र के सहयोग से ग्रामीणों में मत्स्य पालन को लेकर एक नया जोश और संकल्प बढ़ा है। सहकारिता से मछुआरों को उनके कार्य-व्यवसाय में सहयोग मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थितियों में सुधार भी हो रहा है। मछुआरों को सुविधा प्रदान करने वाली सहकारी समितियों के अगले कुछ वर्षों में स्थापित होने से निश्चय ही मत्स्य क्षेत्र से जुड़े वर्गों की व्यावसायिक कुशलता बढ़ेगी और रोजगार सृजन के नए अवसर मिलने से ग्रामीण समुदायों की आर्थिक उन्नति भी होगी। भारत की लंबी समुद्री तटीय जल सीमा और अन्तर्देशीय जल भंडार में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। मछुआरों के जीवन को समृद्ध बनाने में सहकारिता मंत्रालय की यह पहल काफी अहम साबित होगी।

इसके अलवा, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास (एफआईडीएफ) योजना के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र पर विशेष जोर दे रही है। इनके माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में नौ प्रतिशत की सालाना दर से वृद्धि के साथ चालू वित्त वर्ष 2024-25 तक 2.2 करोड़ टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का उद्देश्य मछली उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, मत्स्य उत्पादन के बाद की अवसंरचना और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान

देना है। इस योजना के तहत लाभार्थी कुल परियोजना लागत एवं इकाई लागत का 40 से 60 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि (एफआईडीएफ) का लक्ष्य समुद्री और अन्तर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं तैयार करना है। इस योजना में आइस-प्लांट का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज का विकास, मछली परिवहन और कोल्ड चेन नेटवर्क बुनियादी ढांचे, हैचरी, मछली प्रसंस्करण इकाइयों, मछली चारा मिलों एवं संयंत्रों का विकास और आधुनिक मछली बाजारों का विकास शामिल है।

देश में इस समय प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या 27 हजार से अधिक है और 38 लाख से अधिक सहकार बंधु इनके सदस्य हैं। ये समितियां सदस्यों को ऋण सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही समाज के सबसे हाशिए वाले वर्गों की जरूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करती हैं और उन्हें मछली पकड़ने के उपकरण, मछली के बीज एवं चारे की खरीद में भी सहायता करती हैं। ■

सहकारी क्षेत्र के सहयोग से ग्रामीणों में मत्स्य पालन को लेकर एक नया जोश और संकल्प बढ़ा है। सहकारिता से मछुआरों को उनके कार्य-व्यवसाय में सहयोग मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थितियों में सुधार भी हो रहा है।

खुद को बदलें सहकारी समितियां : मुर्मू

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने तेजी से बदलते समय में सहकारी संस्थाओं को भी अपने आप में बदलाव लाने का सुझाव देते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग, भंडारण क्षमता निर्माण, पर्यटन जैसे नए-नए क्षेत्रों में अवसर तलाशने को कहा है। साथ ही, सहकारिता में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस करने की वकालत की है।

श्री वारणा महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करती राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।

सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सहकारी संस्था किसी के व्यक्तिगत हित और लाभ कमाने का साधन बन कर न रह जाए, नहीं तो कोऑपरेटिव का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। सहकारी समितियों में किसी के एकाधिकार की जगह वास्तविक सहकार होना चाहिए।

युवा सहकार टीम

भारतीय सहकारिता आंदोलन जैसे-जैसे मजबूत होता जा रहा है, नए-नए क्षेत्रों में सहकारी समितियां बनाने और इसके माध्यम से समृद्धि लाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। साथ ही सहकारिता में युवाओं की भागादारी बढ़ाने पर भी फोकस करने से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। सहकारिता क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सहकारी संस्थाओं को जैविक खेती, भंडारण क्षमता निर्माण और पर्यटन जैसे नए-नए क्षेत्रों में अवसर तलाशने की सलाह दी है। उनके मुताबिक, अधिक से अधिक युवाओं को सहकारिता से जोड़ना महत्वपूर्ण हो सकता है। युवा प्रशासन और प्रबंधन में टेक्नोलॉजी को शामिल करके सहकारी संस्थाओं का कायाकल्प कर सकते हैं।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित श्री वारणा महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, 'सहकारी संस्थानों ने गरीबी दूर करने, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अहम योगदान दिया है, लेकिन तेजी से बदलते समय में सहकारी संस्थाओं को भी अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। उन्हें अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए और मैनेजमेंट को प्रोफेशनल बनाना चाहिए। साथ ही सहकारी संस्थाओं को नए-नए क्षेत्रों, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, भंडारण क्षमता निर्माण और पर्यटन में भी आगे आने का प्रयास करना चाहिए।'

व्यक्तिगत लाभ कमाने का साधन न बने कोऑपरेटिव

किसी भी उद्यम की सफलता का असली राज उसका आम लोगों के साथ जुड़ाव है।

सहकारी समितियों में पारदर्शिता की वकालत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता सहकारिता की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। सहकारी संस्थाओं में उनके सदस्यों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सहकारी संस्था किसी के व्यक्तिगत हित और लाभ कमाने का साधन बन कर न रह जाए, नहीं तो कोऑपरेटिव का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। सहकारी समितियों में किसी के एकाधिकार की जगह वास्तविक सहकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में निहित शक्ति का सदुपयोग करने के लिए सहकारिता सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सहकारिता के सिद्धांत संविधान में परिकल्पित न्याय, एकता और भाईचारे की भावना के अनुरूप हैं। जब अलग-अलग वर्गों और विचारधाराओं के लोग सहकार के लिए एकजुट होते हैं, तो उन्हें सामाजिक विविधता का लाभ मिलता है।

विकास में सहकारिता की भूमिका अहम

देश के आर्थिक विकास में सहकारी समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमूल और लिज्जत पापड़ जैसे घरेलू ब्रांड ऐसी सहकारी समितियों के ही उदाहरण हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। इस सफलता में सहकारी समूहों का महत्वपूर्ण योगदान है। आम तौर पर सभी राज्यों में सहकारी समितियां मुख्य रूप से दूध उत्पादों का उत्पादन और वितरण करती हैं। केवल दूध ही नहीं, सहकारी संस्थाएं उर्वरक, कपास, हथकरघा, आवास, खाद्य तेल और चीनी जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज देश में साढ़े आठ लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में तो इसकी जड़ें काफी मजबूत हैं, लेकिन बाकी राज्यों में इसे और मजबूत बनाने की पूरी संभावना है। सहकारिता से युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ना इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। युवा गवर्नेंस और मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का समावेश कर उन संस्थाओं का कायाकल्प कर सकते हैं।

महिलाओं के विकास के बिना किसी भी समाज का विकास असंभव है। महिलाओं को सहकारिता में महत्वपूर्ण भागीदारी देने की वकालत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी समाज के समेकित विकास के लिए उसके सभी सदस्यों का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। महिलाओं की क्षमता और शक्ति में विश्वास जताते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 50 वर्ष पहले श्री विश्वनाथ कोरे उर्फ तात्या साहेब कोरे ने वारणा महिला सहकारी उद्योग समूह की स्थापना की थी। इस समूह ने अनेक उद्यमों के द्वारा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास विश्व पटल पर भारत को ऊंचे स्थान पर पहुंचाएंगे। ■

वारणा ने बंजर भूमि को बनाया समृद्ध

महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर वारणा नदी के तट पर एक हरी-भरी घाटी में स्थित है वारणा नगर जो वारणा समूह की कार्य स्थली है। यह इलाका कभी बंजर हुआ करता था जिसके समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र में परिवर्तन की शुरुआत 1959 में कोडोली गांव के पास एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई। श्री विश्वनाथ कोरे उर्फ तात्यासाहेब कोरे के नेतृत्व में इस सहकारी मिल की स्थापना हुई थी। वारणा सहकारी चीनी मिल द्वारा वारणा घाटी में सहकारी आंदोलन की शुरुआत की गई जिसके परिणामस्वरूप चीनी, दूध और मुर्गी उत्पादन से संबंधित 55 से अधिक सहकारी समितियां बनीं। चीनी मिल वारणा समूह की रीढ़ है। चीनी मिल ने अपनी कार्यकुशलता और उत्पादकता के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। वाराणा समूह को वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड द्वारा भारत में सहकारी चीनी मिलों के बीच चीनी के सबसे बड़े निर्यातक के लिए 'प्रथम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

वारणा समूह समाज के लोगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने में लगा हुआ है। समूह की 55 सहकारी समितियों में यहां के किसानों के परिवार के सदस्य महिला उद्योग और चीनी कारखानों और अन्य संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत हैं। इससे उनके जीवन स्तर में समग्र सुधार हुआ है। भारत के एकीकृत ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर अपने संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से वारणा और उसके आसपास के 78 से अधिक गांवों के सर्वांगीण विकास में यह समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

देश के आर्थिक विकास में सहकारी समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमूल और लिज्जत पापड़ जैसे घरेलू ब्रांड ऐसी सहकारी समितियों के ही उदाहरण हैं।

'सहकारिता में युवाओं की ज्यादा भागीदारी से भारत बनेगा आत्मनिर्भर'

भारतीय सहकारिता क्षेत्र की शीर्ष संस्था भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और दुनिया की नंबर एक सहकारी कंपनी इफको के चेयरमैन **श्री दिलीप संघाणी** सहकारिता क्षेत्र की जानी-मानी हस्ती हैं। श्री संघाणी गुजरात की अमरेली लोकसभा सीट से चार बार सांसद और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान प्रदेश सरकार में सहकारिता, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, गौ-पालन, जेल, आबकारी, कानून एवं न्याय, विधायी एवं संसदीय मामलों के मंत्री रहे हैं। वे गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन भी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में देश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नए-नए अवसर देने और उनकी रोजगार की चुनौतियों का समाधान करने पर खासा जोर दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में भी इसके प्रावधान किए गए हैं। सहकारी क्षेत्र युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहा है और कैसे युवाओं को सहकारी क्षेत्र की ओर प्रेरित किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों सहित नवंबर में भारत में पहली बार आयोजित होने वाले वैश्विक सहकारी सम्मेलन के बारे में **अभिषेक राजा** ने उनसे बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंशः

इफको के चेयरमैन श्री दिलीप संघाणी

देश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर प्रधानमंत्री का खासा जोर है। बजट में भी इसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। सहकारी क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है?

भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया कराना बड़ी चुनौती है। सहकारिता क्षेत्र रोजगार बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बहुत जरूरी है। सहकारिता क्षेत्र की एपेक्स बॉडी होने के नाते एनसीयूआई ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। इसके लिए एनसीयूआई ने युवा कमेटी बनाई है ताकि सहकारिता से जुड़े हर मोर्चे पर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जा सके। साथ ही राज्यों में युवाओं को सहकारिता से जोड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी तरह, इफको में भी युवा डायरेक्टरों को नियुक्त करना शुरू किया गया है। सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की योजनाओं पर नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे वैश्विक सहकारी सम्मेलन में भी विमर्श किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि जब तक युवाओं को महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तब तक युवा सहकारी क्षेत्र की ओर प्रेरित नहीं होंगे। सरकार का भी जोर युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर है। हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सहकारी समितियों के प्रति युवाओं को आकर्षित कर उनकी भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

'सहकार से समृद्धि' का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण पूरी दुनिया के लिए किस तरह कारगर है?

सहकारिता क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने और दुनिया को नई दिशा दिखाने की क्षमता है। आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसमें बिना खून बहाए सहकारिता आंदोलन से ही पूरे विश्व में समृद्धि का द्वार खोला जा सकता है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) और इफको के गठजोड़ से होने वाले वैश्विक सहकारी सम्मेलन से भारतीय सहकारिता क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। देश के आर्थिक विकास और पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में सहकारिता क्षेत्र का बड़ा योगदान होगा। पैक्स का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना हो या फिर पैक्स का कम्प्यूटरीकरण, केंद्रीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में बहुत सारे मूलभूत बदलाव किए गए। देश में सहकार की भावना को प्रोत्साहन मिला है। भारतीय सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी वैश्विक सहकारी क्षेत्र में एक चौथाई फीसदी है। भारतीय सहकारी क्षेत्र मजबूत होगा तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय सहकारी एसोसिएशन (आईसीए) के 130 वर्ष के इतिहास में भारत में नवंबर में पहली बार होगा वैश्विक सहकारी सम्मेलन। सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का होगा आगाज।

वैश्विक सहकारी सम्मेलन से भारतीय सहकारिता क्षेत्र को कितना फायदा होगा और इस दौरान किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे?

भारत में पहली बार आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के वैश्विक सहकारी सम्मेलन से पूरे विश्व में भारतीय सहकारिता की पहचान बढ़ेगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 25-30 नवंबर तक आयोजित होने वाले सम्मेलन में आईसीए के सदस्य देशों के लगभग 1500 प्रतिनिधियों को भारतीय सहकारिता क्षेत्र को जानने का अवसर मिलेगा। इफको 17 अन्य भारतीय सहकारी संगठनों के साथ मिलकर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के विशेष सहयोग और मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान भारतीय सहकारी समितियों को अपनी उपलब्धियों, चुनौतियों और योगदान को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान मिलेगा। इफको की ओर से पूरे विश्व से आए सहकारी बंधुओं के समक्ष भारतीय सहकारिता आंदोलन की उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएंगी। इस दौरान आईसीए की महासभा भी होगी।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में किस तरह के आयोजन होंगे?

केंद्र सरकार द्वारा अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन से देश में सहकारिता क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिला है। वैश्विक सहकारी सम्मेलन का भारत में आयोजन देश के सहकारिता आंदोलन को विश्व में अग्रणी स्थान दिलाएगा। इस सम्मेलन में ही अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आगाज किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान जी-20 सम्मेलन की तर्ज पर देश के विभिन्न राज्यों में बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ऐसे आयोजनों की श्रृंखला शुरू होगी जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में सहकारी क्षेत्र में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। आईसीए के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भारतीय सहकारी संस्थाओं से सहकारिता के गुर सीखेंगे।

इफको की नैनो टेक्नोलॉजी ने वैश्विक फर्टिलाइजर क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत की है। नैनो फर्टिलाइजर को लेकर आगे की क्या योजना है?

इफको ने नैनो (तरल) फर्टिलाइजर, नैनो (तरल) यूरिया और नैनो (तरल) डीएपी के 20 प्रतिशत निर्यात की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी है। अभी तक भारत विभिन्न फर्टिलाइजर का आयात करता रहा है। अगर केंद्र सरकार से अनुमति मिल जाती है तो यह पहली बार होगा जब नैनो फर्टिलाइजर का निर्यात किया जाएगा। इससे जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बचेगी उसका आधा हिस्सा राज्यों को और आधा सहकारी संस्थाओं को दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने 1.90 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की फर्टिलाइजर सब्सिडी दी है। अगर नैनो फर्टिलाइजर का निर्यात बढ़ता है, तो न सिर्फ सब्सिडी बचेगी, बल्कि विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। ■

छोटे लोगों का बड़ा बैंक

एडीसी बैंक के स्वर्णिम शताब्दी महोत्सव में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को गुलदस्ता भेंट करते बैंक के अधिकारी।

अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक बना देश में सबसे अधिक मुनाफा दर्ज करने वाला जिला सहकारी बैंक

बैंक का एनपीए शून्य होना उसकी पारदर्शिता का प्रमाण, सौ साल पहले हुआ था स्थापित

युवा सहकार टीम

गुजरात के अहमदाबाद जिले के दस्करेई में सौ साल पहले एक छोटी सहकारी संस्था 'दस्करेई तालुका कोऑपरेटिव फेडरेशन' सहकारी बैंक 'दस्करेई कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन' के रूप में स्थापित हुई थी। 1937 में इसने 'अहमदाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.' के रूप में काम करना शुरू किया और 1964 से यह 'अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लि.' के नाम से जाना जाने लगा। किसानों की पूंजी की समस्या को सुलझाने के लिए शुरू किया गया यह बैंक आज देश का सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला जिला सहकारी बैंक बन गया है। इसका एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) भी शून्य है जो इसकी पारदर्शिता का प्रमाण है। इसे छोटे लोगों का बड़ा बैंक भी कहा जाता है।

पिछले दिनों इस सहकारी बैंक का स्वर्णिम शताब्दी महोत्सव मनाया गया जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक के 'स्वर्णिम शताब्दी महोत्सव' को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'एडीसी बैंक का 100 साल पूरा होना अहमदाबाद जिले के किसानों के उत्कर्ष के सौ साल की कहानी है। आज यह देश के सबसे मजबूत जिला सहकारी बैंक के तौर पर काम कर रहा है। लगभग शून्य एनपीए, 100 करोड़ रुपये का मुनाफा और 6,500 करोड़ रुपये की जमा राशि वाले एडीसी बैंक की स्थापना के समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यह छोटा सा बीज इतना बड़ा वटवृक्ष बन कर अनेक लोगों का कल्याण करेगा। बैंक ने सौ साल तक कई सोसायटियों, लाखों किसानों और पशुपालकों के जीवन में प्रकाश फैलाने का काम किया है।'

श्री शाह ने कहा, 'जब कोई संस्था कई उतार-चढ़ाव देखते हुए ईमानदारी से काम करके 100 साल पूरा करे, तो यह सिर्फ उस संस्था की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। यह तब और भी अहम हो जाता है जब वह कोई संस्था सहकारी हो जिसका उद्देश्य अपने लिए काम करना नहीं, बल्कि समाज के छोटे-छोटे लोगों को साथ

जोड़कर सामूहिक प्रगति करने का हो।' आज किसानों के लिए कई तरह की कृषि सहायता सरलता से उपलब्ध हैं, लेकिन जब इस बैंक की स्थापना हुई थी तब किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। किसानों के पास साहूकारों से ज्यादा ब्याज पर पैसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके लिए उन्हें अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ती थी। यदि कभी सूखा पड़ता था और किसान उनके पैसे नहीं चुका पाते थे, तो साहूकार उस जमीन को कब्जा लेता था और किसान खेतिहर मजदूर बन जाता था।

श्री शाह अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। उन दिनों की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने बताया कि चेयरमैन होने के नाते जब वे गांवों में जाते थे, तो लोग कहते थे कि यह छोटे लोगों का बड़ा बैंक है। एडीसी ने छोटे लोगों का बड़ा बैंक के मंत्र को सही मायने में चरितार्थ किया है। उन्होंने कहा कि कम पूंजी वाले कई लोगों को इकट्ठा करके बड़ी पूंजी का रूप देकर उन्हें काम करने का प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, उन्हें समृद्ध करना और उनके सम्मान पूर्ण जीवन की व्यवस्था करना ही सहकार है।

एक समय यह बैंक काफी मुश्किलों से गुजर रहा था और आज यह भारत में सबसे अधिक मुनाफा दर्ज करने वाला जिला सहकारी बैंक है। इस बैंक के सफल होने में सेवा सहकारी सोसायटियों का बड़ा योगदान है। श्री शाह के मुताबिक सेवा सहकारी सोसायटियों के कामकाज में कई तरह के प्रशासनिक अवरोध थे, लेकिन पिछले तीन साल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सारे अवरोध दूर किए हैं। अब ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सेवा सहकारी सोसायटियों के पास गोदाम हो, उनका कम्प्यूटराइजेशन हो, उन्हें शून्य ब्याज पर ऋण मिले, सेवा सहकारी सोसायटी जल समिति चला सके, गैस सिलेंडर की एजेंसी ले सकें और पेट्रोल पंप का संचालन कर सकें। आज देश की सभी सेवा सहकारी मंडलियां एक ही तरह के नियमों और अकाउंटिंग सिस्टम से चल रही हैं। आने वाले दिनों में सेवा सहकारी मंडली ग्रामीण स्तर पर वाइब्रेंट यूनिट बनेंगी। इनमें कम्युनिटी सर्विस सेंटर भी खोले जा रहे हैं। सेवा सहकार सोसायटी केंद्र और राज्य सरकार की 300 तरह की योजनाओं का लाभ पाने का स्थान बनीं जिससे सहकारिता आंदोलन अधिक मजबूत हुआ है।

श्री शाह ने कहा कि 120 साल पहले जब भारत में सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ, उस समय इस क्षेत्र की जितनी सापेक्षता थी, उससे ज्यादा सापेक्षता आज है। देश में इसके कई सफल उदाहरण हैं। उन्होंने गुजरात के अमूल का उदाहरण देते हुए कहा कि अमूल से जुड़कर 35 लाख महिलाओं को रोजगार मिला है। आज अमूल का टर्नओवर 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि एडीसी बैंक ने गांधीनगर और अहमदाबाद के विकास के लिए काफी अच्छे काम किए हैं। बैंक की जिम्मेदारी है कि वह पूरे जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के विषयों को लेकर तमाम सहकारी संस्थाओं को एकजुट करे और एक कार्य योजना बनाकर हर गांव में उसे लागू करे। उन्होंने कहा कि एडीसी बैंक द्वारा बनाए गए कई तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भारत सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से स्वीकार कर देश के सभी बैंक को देने का निर्णय किया। बैंक ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का समान रूप से निर्वहन किया है। एडीसी बैंक का एनपीए लगभग शून्य होना इस बात का प्रमाण है कि यह बैंक कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। ■

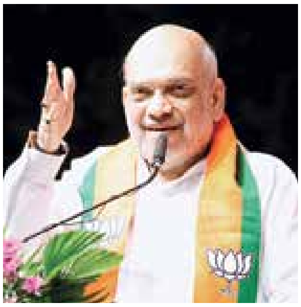

कम पूंजी वाले कई लोगों को इकट्ठा कर बड़ी पूंजी का रूप देकर उन्हें काम करने का प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, उन्हें समृद्ध करना और उनके सम्मान पूर्ण जीवन की व्यवस्था करना ही सहकार है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

युवाओं को सहकारिता से जोड़ने में जुटा कृभको

एजीएम को संबोधित करते कृभको के चेयरमैन डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव।

वित्त वर्ष 2023-24 में कृभको ने कमाया 334.12 करोड़ रुपये का कर पूर्व मुनाफा, 20 प्रतिशत लाभांश की घोषणा

युवा सहकार टीम

सहकारिता क्षेत्र की प्रमुख उर्वरक उत्पादन समिति कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) युवाओं को सहकारिता क्षेत्र से जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए कृभको ने सहायक समितियों के साथ मिलकर नए क्षेत्रों में कदम रख रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में काम करना शुरू किया है। कृभको चेयरमैन डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव के मुताबिक युवा अगर उत्पादन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी फोकस करें तो सहकारिता क्षेत्र में उनके लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। डॉ. यादव ने युवा सहकार से बातचीत में कहा, 'रोजगार के लिए भटकने वाले युवा सहकारी समितियों से जुड़कर न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, बल्कि और लोगों को भी अपने साथ जोड़कर उनके लिए नया रास्ता खोल सकते हैं। सहकारी समिति बनाकर वे फसल एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन सहित उनकी मार्केटिंग कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इससे सहकारिता आंदोलन को तो मजबूती मिलेगी ही, सहकार से समृद्धि की संकल्पना भी साकार होगी।'

पिछले दिनों इस प्रमुख उर्वरक सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉ. यादव ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में कृभको ने 334.12 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ कमया है। इसके साथ ही समिति ने वित्तीय वर्ष के लिए अपनी इक्विटी पूंजी पर 20 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया है। कृभको की 44वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन एनसीयूआई के दिल्ली स्थित सभागार में किया गया। आम सभा की बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और देशभर की सहकारी समितियों के सदस्य व प्रतिनिधि उपस्थित थे। कृभको ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूरिया का बेहतर उत्पादन किया। इस दौरान 23.35 लाख टन यूरिया और 13.88 टन अमोनिया का उत्पादन हुआ जो क्रमशः 106.4 प्रतिशत और 111.32 प्रतिशत की क्षमता के उपयोग को दशार्ता है।

किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कृभको ने नीम कोटेड यूरिया, आयातित डीएपी, एमएपी, एमओपी, सघन उर्वरकों, बायो उर्वरकों, कंपोस्ट, प्रमाणित बीज, हाईब्रिड बीज, एसएसपी, जिंक सल्फेट, प्राकृतिक पोटाश और समुद्री शैवाल व फोर्टिफायड जैव उत्तेजकों को भी लांच किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृभको ने 52.82 लाख टन उर्वरक की बिक्री की जिसमें यूरिया और सघन उर्वरक भी शामिल हैं। कृभको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहकारी

समिति कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (केएफएल) ने अपनी क्षमता का 123.23 और 130.46 प्रतिशत उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष में 10.66 लाख टन यूरिया और 6.54 लाख टन अमोनिया का उत्पादन किया। केएफएल ने 14.40 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृभको ने सहायक समितियों के साथ मिल कर नये क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया है। कृभको एग्री बिजनेस लिमिटेड (केएबीएल) और कृभको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केएबीएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में चावल, मिर्च, बाजरा, मखाना और दालों का घरेलू और अंतराष्ट्रीय व्यापार कर 821 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया है। इस बीच कृभको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुजरात के हजीरा और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में जैव एथेनॉल के दो नये प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है।

कृभको ने अपने समर्पित कृषि विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक ट्रांसफर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अन्य ग्रामीण कल्याणकारी कार्यकलाप करके कृषक समुदाय के लाभ एवं आजीविका में सुधार किया है। सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना एवं ग्रामीण विकास करना कृभको की हमेशा से पहली प्राथमिकता रही है।

वार्षिक आम सभा की बैठक में कृभको ने सहकारिता क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली और सहकारिता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली दो सहकारी समितियों को सम्मानित भी किया। बिहार के श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह को कृभको सहकारिता शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के श्री वीकेएसके सेंथिल कुमार को कृभको सहकारिता विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ■

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृभको ने सहायक समितियों के साथ मिल कर नये क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया है। कृभको एग्री बिजनेस लिमिटेड (केएबीएल) और कृभको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कौशल से सशक्त युवा ही बनाएंगे विकसित भारत

पुणे में आयोजित रोजगार मेले के उद्घाटन के मौके पर समारोह को संबोधित करते केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल।

विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए युवा पीढ़ी का सक्षम, आत्मनिर्भर, उद्यमशील, साक्षर और कुशल होना जरूरी

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ-साथ स्वरोजगार और कौशल विकास को प्राथमिकता

अंतरराष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र के माध्यम से भारतीय युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के अवसर दिलाने की केंद्र ने की पहल

युवा सहकार टीम

केंद्र सरकार ने युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार लायक बनाने की महत्वाकांक्षी पहल की है। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास, भारतीय ज्ञान परंपराओं पर आधारित शिक्षा, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ-साथ स्वरोजगार और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। पुणे में प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए युवा पीढ़ी का सक्षम, आत्मनिर्भर, उद्यमशील, साक्षर और कुशल होना जरूरी है।

पुणे के छत्रपति शिवाजी नगर स्थित माडर्न कॉलेज में यह मेला कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता विभाग और समर्थ युवा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। समर्थ युवा फाउंडेशन युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल करता रहता है। फाउंडेशन के पहलों की सराहना करते हुए मुरलीधर मोहोल ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के एक करोड़ युवाओं को जॉब ट्रेनिंग के लिए देश की बड़ी कंपनियों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों से एमओयू (समझौता ज्ञापन) किए जा रहे हैं। इसके तहत पुणे में एक अंतरराष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ युवा उठाएं और अपनी एवं देश की प्रगति का संकल्प लें।

महिलाओं को भी मिले कौशल आधारित अवसर

इस मौके पर महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदा पाटिल ने महिलाओं के लिए कौशल आधारित अवसर पैदा करने की वकालत करते हुए कहा, 'परिवारों की वित्तीय जरूरतों के लिए युवाओं के साथ-साथ महिलाओं के लिए कौशल आधारित अवसर पैदा करना जरूरी है। यह देखा जाना चाहिए कि घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए उनके लिए घर पर ही कौशल आधारित रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे। कौशल विकास के माध्यम से अच्छी आय के साथ आर्थिक उन्नति होती है। दुनिया भर में कुशल जनशक्ति के लिए एक बड़ा अवसर है। युवाओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों का कौशल विकास होगा, तो उन्हें ये अवसर उपलब्ध होंगे।'

जर्मनी जाएंगे महाराष्ट्र के 10 हजार युवा

रोजगार मेले के उद्घाटन मौके पर महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि भारत की तुलना में विदेश में आर्थिक लाभ ज्यादा है। इसलिए राज्य सरकार ने जर्मनी के बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके युवाओं के लिए अच्छे अवसर पैदा करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि यदि युवा खुश रहेगा तो परिवार खुश रहेगा। युवा भारत की शक्ति है। पहले चरण में 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित कर जर्मनी भेजने की योजना है। इसके लिए जर्मन भाषा सीखना जरूरी है। पहले जर्मन भाषा अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब मराठी के माध्यम से जर्मन भाषा सिखाने का प्रयोग शुरू किया जा रहा है।

सकारात्मक बनें युवा

महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. नीलम गोरे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा रोजगार के अवसर पैदा करती है। युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए सकारात्मक रहना चाहिए। विदेश में नौकरी के कई अवसर उपलब्ध हैं। इसके लिए यहां के युवाओं को अलग-अलग देशों की भाषाएं सीखनी चाहिए और कौशल हासिल करना चाहिए। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक एक्शन फोर्स बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को विदेशों में विभिन्न पदों पर जाने के लिए दृढ़ संकल्प और दृढ़ता रखनी चाहिए।

अवसरों का उठाएं लाभ

पुणे के कलेक्टर डॉ. सुहार दिवसे ने कहा कि आज रोजगार और स्वरोजगार एक अहम मुद्दा है। पुणे शिक्षा का घर और आईटी हब है। आज रोजगार बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। युवाओं को खुद को कौशल से सशक्त बनाकर इन अवसरों का लाभ उठाने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा कर्तव्य योजना का लाभ उठाने की अपील की।

7,200 लोगों ने दिया इंटरव्यू

समर्थ युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने एवं स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह रोजगार मेला आयोजित किया गया है। इसमें 131 कंपनियों और प्रतिष्ठानों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है और 18,257 रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि मेले में लगभग 9,500 जरूरतमंद लोगों ने विभिन्न स्टालों का दौरा किया, जबकि 7,200 लोगों ने नौकरी के लिए साक्षात्कार दिया। इसी के अनुरूप चयन प्रक्रिया की गई।

इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के वीडियो संदेश भी दिखाए गए। पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, कौशल विकास विभाग की संभागीय उपायुक्त अनुपमा पवार, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक रमाकांत भावसार भी उदघाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे। ■

परिवारों की वित्तीय जरूरतों के लिए युवाओं के साथ-साथ महिलाओं के लिए कौशल आधारित अवसर पैदा करना जरूरी है। यह देखा जाना चाहिए कि घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए उनके लिए घर पर ही कौशल आधारित रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे।

पुणे में अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू

युवा सहकार टीम

दुनिया भर के कई विकसित देश कुशल जनशक्ति की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर, भारत दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश के रूप में नई पहचान बना रहा है। इन दोनों चीजों का समन्वय करके भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) इंटरनेशनल नामक एक अलग विभाग बनाया है। यह विभाग दुनिया भर के विभिन्न देशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को ठीक से समझने के बाद भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए देश भर में अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर रहा है।

समर्थ युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश पांडे (बीच में) व अन्य।

एनएसडीसी इंटरनेशनल का महाराष्ट्र में पहला अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र पुणे शहर के शिवाजी नगर में तंत्र निकेतन के परिसर में शुरू किया गया है। इस केंद्र में प्रथम चरण में हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और ब्यूटी एंड वेलनेस क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को विदेशी भाषाओं और संस्कृति का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र विदेशों में नौकरी दिलाने के बहाने प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा लोगों से जबरन वसूली और धोखाधड़ी करने पर भी अंकुश लगाएंगे। चूंकि भारत सरकार की केंद्रीय स्तर की प्रणाली एनएसडीसी इंटरनेशनल इसमें सक्रिय है, इसलिए सुरक्षा और विश्वसनीयता बनी रहेगी। इससे भारतीय युवाओं और महिलाओं को वैश्विक रोजगार के अवसर बहुत आसानी से प्रदान किए जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप विश्व स्तरीय कौशल के साथ भारतीय युवा पीढ़ी अपने व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास में भी अधिक प्रभावी ढंग से योगदान देने के लिए तैयार होगी। ■

वीजा ने टीएचएससी से मिलाया हाथ

पर्यटन कौशल से लैस होंगे 20 हजार युवा

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी और वीजा की उपाध्यक्ष केली महोन टुलियर की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

युवा सहकार टीम

लोगों की आमदनी जैसे-जैसे बढ़ रही है वे पर्यटन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। बढ़ते पर्यटन को देखते हुए इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही है। मगर इस क्षेत्र में अभी भी कुशल लोगों की संख्या बहुत कम है। युवाओं को पर्यटन कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन आने वाले टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल (टीएचएससी) ने बहुराष्ट्रीय कार्ड एवं डिजिटल भुगतान कंपनी वीजा के साथ एमओयू (समझौता ज्ञापन) किया है। 10 लाख अमेरिकी डॉलर के इस एमओयू के माध्यम से देश के 10 राज्यों के 20,000 युवाओं को पर्यटन संबंधित कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा।

दुनिया भर में कुशल जनशक्ति के लिए रोजगार के नए-नए अवसर खुल रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाने में भारत पीछे नहीं रह सकता। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों से एमओयू (समझौता ज्ञापन) किए जा रहे हैं। यह एमओयू उसी रणनीति का हिस्सा है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी और वीजा की उपाध्यक्ष, चीफ पीपुल और कॉर्पोरेट मामले अधिकारी केली महोन टुलियर की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पर्यटन मंत्रालय के साथ वीजा के चल रहे सहयोग पर आधारित इस साझेदारी का उद्देश्य असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों में युवाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि पर्यटकों के लिए पर्यटन सेवा अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। यह कार्यक्रम

वीजा और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर के तीन वर्षीय साझेदारी पर किए हस्ताक्षर

साझेदारी के तहत 10 राज्यों में 20,000 भारतीय युवाओं को पर्यटन से संबंधित कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा

घरेलू पर्यटन उद्योग में आवश्यक भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे- टूर गाइड, ग्राहक सेवा अधिकारी, प्रकृतिवादी और पैराग्लाइडिंग पायलट आदि।

इस मौके पर जयंत चौधरी ने कहा, 'भारतीय पर्यटन उद्योग में आर्थिक विकास को गति देने और देश में लाखों नौकरियां पैदा करने की अपार क्षमता है। वीजा के साथ यह साझेदारी उस क्षमता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमारे युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में सफल होने और भारत को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेगी। यह समन्वय युवा भारतीयों को उनके भविष्य को आकार देने और देश की विकास की कहानी में योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल और अवसरों से सशक्त बनाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दशार्ता है।'

वीजा की उपाध्यक्ष, चीफ पीपुल और कॉर्पोरेट मामले अधिकारी केली महोन टुलियर ने कहा, 'पर्यटन उद्योग में सफल होने के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करके हमारा उद्देश्य न केवल उनके लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है, बल्कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए समग्र अनुभव को बेहतर बनाना भी है। टीएचएससी के साथ साझेदारी और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का समर्थन प्रतिभाओं को पोषित करके और भारत को वैश्विक पर्यटकों के लिए एक शीर्ष गंतव्य बनाने के सरकार के प्रति वीजा की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।'

पर्यटन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 231 अरब डॉलर से अधिक है। वर्ष 2023 में इस क्षेत्र ने 4.2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। वीजा ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के पर्यटन परिदृश्य को मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। वीजा ने अपने डेटा और एनालिटिक्स विशेषज्ञता के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय को मूल्यवान डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करके इनबाउंड पर्यटन को बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। इससे वैश्विक मंच पर भारत के विविध स्थलों को बढ़ावा देने में मदद मिली है। वीजा डिजिटल भुगतान में दुनिया भर में अग्रणी है, जो 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में उपभोक्ताओं, व्यापारियों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी संस्थाओं के बीच लेन-देन को सुविधाजनक बनाता है। ■

स्विगी से भी एमओयू

युवा सहकार टीम

विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। इसके तहत स्विगी के त्वरित नेटवर्क के भीतर कौशल और रोजगार के अवसरों की एक श्रृंखला की पेशकश करते हुए 'स्विगी स्किल्स' नाम की पहल शुरू की गई है। यह पहल रेस्तरां संचालन और खुदरा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में लोगों के लिए रोजगार, इंटर्नशिप और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगी। 'स्विगी स्किल्स' पहल के तहत स्विगी पार्टनर प्लेटफॉर्म को स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) के साथ एकीकृत किया जाएगा जो स्विगी में कार्यरत श्रमशक्ति के लिए ऑनलाइन कौशल विकास संबंधी पाठ्यक्रम, प्रमाणन और प्रशिक्षण मॉड्यूल को सुलभ बनाएगा। इस साझेदारी से स्विगी से जुड़े 2.4 लाख डिलीवरी पार्टनर्स और रेस्तरां पार्टनर्स के कर्मचारियों को लाभ होगा।

इस पहल और साझेदारी के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने कहा, 'भारत के लिए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अहम भूमिका निभाएंगे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र के लिए 300 से अधिक पहल और 80 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए जा रहे हैं। हम इस क्षेत्र में विकास के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम भी तैयार कर रहे हैं जहां कौशल और शिक्षा साथ-साथ काम करेंगे। हम चाहते हैं कि और अधिक संख्या में कॉरपोरेट हमारे साथ जुड़ें।'

स्विगी एक प्रमुख घरेलू और उपभोक्ता ब्रांड है, जो लगभग 700 शहरों में काम कर रहा है। इसके पास वितरण अधिकारियों और रेस्तरां भागीदारों का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है। इस साझेदारी पर स्विगी फूड मार्केटप्लेस के सीईओ रोहित कपूर ने कहा, 'हम अपने साझेदारों के ऐप्स में स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) के साथ एकीकरण करने की योजना बना रहे हैं, जिससे लगभग 2.4 लाख डिलीवरी पार्टनर और हमारे 2 लाख रेस्तरां पार्टनर के कर्मचारी आसानी से ऑनलाइन कौशल विकास पाठ्यक्रम, ऑफलाइन प्रमाणन और प्रशिक्षण मॉड्यूल तक पहुंचने में सक्षम होंगे।' ■

क्रेडिट सोसायटियों से मिलेगा दोगुना लोन

युवा सहकार टीम

दिल्ली की सहकारी समितियों के सदस्य अब क्रेडिट सोसायटियों से पहले की तुलना में ज्यादा लोन ले पाएंगे। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने कर्ज सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसकी मांग काफी समय से की जा रही थी। इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक, सहकारी समितियों के सामान्य सदस्य अब 4 लाख रुपये तक का लोन ले पाएंगे जो पहले की तुलना में दोगुना है। पहले इन सदस्यों के लिए कर्ज की सीमा 2 लाख रुपये थी। इसी तरह, वेतनभोगी सदस्यों को अब 5 लाख रुपये तक का लोन मिल पाएगा जिसकी सीमा पहले 3 लाख रुपये थी।

दिल्ली में पिछले दस वर्षों से क्रेडिट सोसायटियों की कर्ज सीमा में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। कर्ज की राशि में बढ़ोतरी से दिल्ली की सैकड़ों क्रेडिट सोसायटियों और उनके सदस्यों को फायदा होगा, जो विभिन्न जरूरी खर्चों के लिए इन ऋणों पर निर्भर रहते हैं। कई सदस्य विवाह, बीमारी के इलाज और अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए इनसे कर्ज लेते हैं। सहकार भारती से जुड़े यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड (यूटीसीएसएफ) की ओर से काफी समय से क्रेडिट सोसायटियों की कर्ज सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि क्रेडिट सोसायटियों की कर्ज सीमा में पिछले दस वर्ष से कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि इस दौरान मुद्रास्फीति और खर्चों में वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान औसत मुद्रस्फीति दर 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। इससे जीवनयापन की लागत और ज्यादा राशि वाले कर्ज की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नई कर्ज सीमा का उद्देश्य इस असंतुलन को ठीक करना है ताकि सहकारी क्षेत्र को वित्तीय राहत मिल सके। ऐसे में सामान्य सदस्यों के लिए कर्ज सीमा बढ़ाकर 4 लाख रुपये और वेतनभोगी सदस्यों के लिए बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। आदेश के मुताबिक, सामान्य बचत और ऋण समितियों में ऋण की सीमा सदस्यों के चुकता शेयरों के मूल्य का 20 गुना होगी। वेतनभोगी सदस्यों के लिए यह 25 गुना तक बढ़ाई जा सकती है।

यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड ने इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। संगठन का कहना है कि यह कदम दिल्ली में सहकारी आंदोलन को मजबूत करेगा। यह महासंघ की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। महासंघ भविष्य में भी सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। ■

सहकारी समितियों के सामान्य सदस्य अब 4 लाख रुपये तक का लोन ले पाएंगे जो पहले की तुलना में दोगुना है। पहले इन सदस्यों के लिए कर्ज की सीमा 2 लाख रुपये थी। इसी तरह, वेतनभोगी सदस्यों को अब 5 लाख रुपये तक का लोन मिल पाएगा जिसकी सीमा पहले 3 लाख रुपये थी।

गांवों में होमस्टे से खुले रोजगार के अवसर

परियोजना के लक्ष्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना ताकि पलायन को कम किया जाए
- गांव के विकास में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना तथा महिलाओं का सशक्तिकरण करना
- इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है कि इस योजना की प्रत्यक्ष लाभार्थी महिलाएं ही हों
- शहरी लोगों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों को भी भारत की समृद्ध ग्रामीण संस्कृति एवं परंपराओं से परिचित कराना
- होमस्टे के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से रोजगार सृजन करना

युवा सहकार टीम

शहरों के व्यस्त और भागदौड़ भरे जीवन से सुकून पाने की इच्छा ने देश में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। इससे न सिर्फ शहरी पर्यटकों को ग्रामीण जन-जीवन से परिचित होने का अवसर मिलता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। पर्यटन क्षेत्र में उभर रही इन संभावनाओं को अवसर में बदलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पर्यटन की एक अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कुल 500 गांवों को पर्यटन गांव बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें 400 जनजातीय गांव होंगे। इसके तहत शहरी और विदेशी पर्यटकों के लिए गांवों में होमस्टे खोले जा रहे हैं। यह स्थानीय लोगों के लिए अतिरिक्त आमदनी सृजित करने का नया जरिया बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस परियोजना में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने और उन्हें इसके लिए तैयार करने में नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी

लिमिटेड (एनवाईसीएस) महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है।

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को कम किया जा सके। साथ ही गांव के विकास में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना तथा महिलाओं का सशक्तिकरण करना भी इस योजना का हिस्सा है। इस योजना में इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है कि योजना की प्रत्यक्ष लाभार्थी महिलाएं ही हों। शहरी तथा विदेशी पर्यटकों को भारत की समृद्ध ग्रामीण संस्कृति एवं परंपराओं, विशेष कर जनजातीय संस्कृति एवं परम्पराओं से परिचित कराने के लिए होमस्टे के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से रोजगार का सृजन हो रहा है।

एनवाईसीएस ने कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था बैक टू विलेज (बी2वी) के साथ मिलकर दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया था। बैक टू विलेज के संस्थापक मनीष कुमार हैं जो नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के उपाध्यक्ष भी हैं। इस एमओयू के आधार पर सितंबर 2022 में बैतूल एवं छिंदवाड़ा जिले में एक-एक गांव आवंटित किए गए। बाद में बैतूल जिले के दो और गांव आवंटित हुए। एनवाईसीएस और बी2वी बैतूल के बज्जरवाड़ा, बांचा एवं कान्हावाड़ी गांव और छिंदवाड़ा के देवगढ़ गांव में ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं। कान्हावाड़ी गांव दो महीने पहले ही आवंटित हुआ है। बाकी तीन गांव 1-2 वर्ष पहले आवंटित हुए थे।

बैक टू विलेज के संस्थापक मनीष कुमार

इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में न्यूनतम 10 होमस्टे के निर्माण के लिए योग्य लाभार्थी का चयन कर होमस्टे का निर्माण करवाया जा रहा है। तीन होमस्टे निर्मित हो चुके हैं, जबकि 22 का निर्माण कार्य चल रहा है। पांच का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। जिनका निर्माण पूरा हो चुका है उनका संचालन शुरू हो चुका है। इनमें पर्यटकों का आना प्रारंभ हो चुका है। होमस्टे के निर्माण में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से प्रत्येक जनजाति लाभार्थी को 60 प्रतिशत तथा अन्य लाभार्थी को 40 प्रतिशत अनुदान मिलता है। इसके तहत गांव के आस-पास के पर्यटन एवं पिकनिक वाली जगहों को चिन्हित कर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर आधारित समूह बनाना एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे- लोकगीत, लोकनृत्य, हस्तशिल्प एवं हस्तकला, भजन- कीर्तन, पर्व-त्योहार, गाइड (कृषि, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर) आदि। ये सभी

गतिविधियां सभी आवंटित गांवों में नियमित रूप से चल रही हैं। इन गतिविधियों में उन गांवों के लोगों के अलावा दूसरे गांवों के लोग में भागीदार बन रहे हैं। साथ ही हस्तशिल्प की मार्केटिंग एवं बिक्री की जाती है।

पूर्व में आवंटित तीनों गांवों में प्रत्येक गांव में 10-10 लाभार्थियों का चयन कर उनका दूसरे होमस्टे में एक्सपोजर विजिट करवाया गया। इसके बाद उनके होमस्टे का निर्माण प्रारंभ हुआ। यह अपने आप में एक अलग प्रकार की परियोजना है, इसलिए एनवाईसीएस के साथ-साथ लाभार्थियों को भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना के माध्यम से एनवाईसीएस एवं बी2वी रोजगार के नए-नए अवसर पैदा कर पारंपरिक रोजगार को भी संवर्द्धित कर रही है। इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। देवगढ़ (छिंदवाड़ा) के एक होमस्टे के मालिक ने गांव के कुम्हार कैलाश प्रजापति को एक साथ मिट्टी के 100 गमलों का ऑर्डर दिया। इस पर उसकी प्रतिक्रिया सबको अतिउत्साहित करने वाली थी। कैलाश प्रजापति का कहना था कि पिछले कई वर्षों में उसे इस प्रकार का बड़ा ऑर्डर नहीं मिला था। इसलिए उसके मन में बार-बार यह बात आती थी कि इस काम को छोड़कर मजदूरी कर ली जाए ताकि रोजी-रोटी का इंतजाम हो सके।

इसी तरह, एनवाईसीएस ने ग्रामीणों को रसायनमुक्त प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया और महिलाओं को अपने घर की बाड़ी में ऑर्गेनिक किचन गार्डन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। जब किचन गार्डन से उनकी आवश्यकता से अधिक सब्जियां उगने लगी तो महिलाएं स्वयं ही उन अतिरिक्त सब्जियों को सड़क किनारे बैठ कर बेचने लगी। इस से न सिर्फ उनके घर की सब्जियों का खर्च बचा, बल्कि उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी। पिछले दो वर्षों में लगभग ऐसे सौ परिवारों ने किचन गार्डन के माध्यम से कुल 10 लाख रुपये से अधिक की बचत की है। ■

Did You Know?

2025 is the International Year of Cooperatives!

The UN declared 2025 as a year to celebrate cooperatives around the world. Cooperatives are businesses owned by their members, focusing on both profit and the needs of their communities. They play a big role in sustainable development and achieving the UN's Sustainable Development Goals by 2030.

There will be a year-long celebration to raise awareness about cooperatives and their positive impact.

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO UREA PLUS
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"